जो मजदूरी नहीं करता लेकिन खाता है, वह चोरी का अन्न खाता है।
-महात्मा गांधी-

दैनिक
लोक जीवन
www.lokjeewan.com
जयपुर एवं भीलवाड़ा से प्रकाशित राज्य स्तरीय समाचार पत्र
संस्थापक - स्व. डॉ. शिवकुमार जी त्रिवेदी

लोक जीवन में विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें:-
- : जयपुर : -
0141-4038281
- : भीलवाड़ा : -
8306792625

वर्ष- 19 | अंक- 186 | जयपुर. मंगलवार . | 03 नवम्बर , 2026 | RNI No. RAJHIN/2008/26744 | मूल्य 1 रूपया | पृष्ठ - 4

न्यूज इनबॉक्स

पंजाब में 'आप' को बड़ा झटका, तीन विधायक भाजपा में शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब में आम आदमी पार्टी के तीनों विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, चेतन सिंह जोड़ामाजरा और कुंवर विजय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तीनों विधायक सुबह दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे। तीनों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी का कारवां दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाई रिटायर्ड आईजी और अमृतसर पूर्व (उत्तर) से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, उनके साथ समाना से विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सरदार चेतन सिंह जोड़ामाजरा और सनौर से विधायक मेरे भाई हरमीत सिंह पठानमाजरा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस विजन के साथ वे हमारे साथ जुड़े हैं, उसका पूरा सम्मान किया जाएगा और उन्हें पूरा मान-सम्मान और गरिमा मिलेगी। आम आदमी पार्टी की डूबती हुई नाव से समझदार नेता और विधायक बाहर निकलकर हमारे पास आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं।' बीजेपी में शामिल होने के बाद कुंवर विजय प्रताप ने कहा, 'पंजाब में आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने खुद ही इसका अंत कर दिया है। व्यावहारिक रूप से, अब आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। पंजाब में भी 'डबल इंजन' की सरकार बनेगी।' वहीं, हरमीत सिंह पठानमाजरा ने कहा, 'जब आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब आई थी, तो उन्होंने एक बहुत ही प्रभावशाली विजन पेश किया था।

40 विला खरीद मामले में आईएएस शिखर अग्रवाल को नोटिस

जयपुर (कासं)। एक ही कंपनी से 40 विला-कॉटेज खरीदने के मामले में आईएएस शिखर अग्रवाल को सरकार ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्मिक विभाग ने कारण बताओ नोटिस पर एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इधर, शिखर अग्रवाल ने जिस कंपनी से विला खरीदे उसके सभी सरकारी फायदों पर एसीबी जांच होने तक रोक लगा दी है। 30 अक्टूबर को जारी किए गए नोटिस में आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम खरीदे गए विला को प्रॉपर्टी रिटर्न में नहीं दिखाने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। खुलासे के बाद शिखर और प्रशाखा को उनके पदों से हटाकर एपीओ किया जा चुका है। शिखर अग्रवाल के खिलाफ एसीबी शनिवार (31 अक्टूबर) को ही पीई दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर चुकी है। शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर ने जिस कंपनी से 40 विला और कॉटेज खरीदे उसको निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाले सरकारी फायदों पर रोक लगा दी है। गोयल फैशन्स प्रा. लि. को मंजूर सरकारी लाभों पर एसीबी की प्रारंभिक जांच पूरी होने तक रोक लगाई गई है। कंपनी को जांच पूरी होने तक मिलेगा निवेश प्रोत्साहन और किसी छूट का लाभ नहीं होगा। सीएम के निर्देशों के बाद आयुक्त उद्योग वाणिज्य कार्यालय ने इसके आदेश जारी किए हैं। आईएएस शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर को एसीबी जल्द नोटिस जारी कर बुलाने की तैयारी में है। एसीबी ने सोमवार को उदयपुर कलेक्टर और सब-रजिस्ट्रार, अलवर सब-रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए। इनसे जानकारी मांगी गई है। वहीं DOP को नोटिस जारी कर IR और जीए 55 (प्रॉपर्टी रिटर्न) की पूरी जानकारी मांगी गई है। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) की जानकारी मांगी गई है।

'कोर्ट को हल्के में मत लीजिए', नोरा फतेही को फिर समन

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही को फिर से समन जारी किया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान उनके वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि नोरा का बर्ताव ठीक नहीं है और कोर्ट को हल्के में मत लीजिए। कोर्ट ने कहा कि नोरा इस मामले में अभियोजन पक्ष की गवाह हैं और उन्हें सबूत दर्ज कराने के लिए अदालत में मौजूद रहना चाहिए था। विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने उन्हें 6 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले नोरा की ओर से पेश वकील ने अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की अर्जी लगाई थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि गवाह होने के नाते उन्हें अदालत में आना चाहिए था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि नोरा फतेही को समन भेजा गया था, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वह पेश होंगी या नहीं। इसके बाद नोरा के वकील ने उनकी ओर से छूट की मांग की। कोर्ट ने वकील से पूछा कि नोरा को समन कब भेजा गया था। इस पर वकील ने बताया कि उन्हें 29 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद उनके अदालत में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने साफ कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। नोरा को इस मामले में अभियोजन पक्ष की गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराना है। इससे पहले भी उन्हें इस मामले में जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बुलाया था। यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जिस पर दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान करीब 200 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने का आरोप है। आरोप है कि सुकेश ने खुद को केंद्र सरकार का सीनियर अधिकारी बताकर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से पैसे ऐंठे थे।

11 केवी लाइन की चपेट में आई मिक्सर मशीन, 8 की मौत



जयपुर (कासं)। झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के छापोली गांव में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। जिस रास्ते को बनवाने के लिए गांव के लोगों ने आपस में चंदा जुटाया, उसी सड़क का निर्माण आठ परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दर्द बन गया। ग्रामीण सीमेंट मिक्सर मशीन को धक्का देकर दूसरी जगह ले जा रहे थे, तभी मशीन ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवी की बिजली लाइन के संपर्क में आ गई। हादसा इतना भीषण था कि आठ मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल उदयपुरवाटी सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। एक साथ आठ मजदूरों की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। इससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और हालात संभालने में जुट गईं। उदयपुरवाटी एसएचओ रामपाल ने बताया, बजरी मिलाने के काम में लगी एक मशीन ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई थी। इससे मशीन में करंट दौड़ गया और वहां काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। हादसे में सड़क निर्माण का काम करने वाले ठेकेदार विष्णु सैनी की भी मौत हो गई। 7 घंटे बाद शाम 5 बजे मुआवजा और संविदा पर नौकरी के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक, तीर्थस्थल कदम कुंड जाने वाला रास्ता लंबे समय से खराब था। गांव के लोगों ने सरकारी मदद का इंतजार करने के बजाय आपस में चंदा इकट्ठा कर सीसी सड़क बनवाने का फैसला किया। करीब तीन-चार महीने से निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन बीच-बीच में रुक जाता था। सोमवार को भी काम दोबारा शुरू हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार विष्णु सैनी से हाथ जोड़कर काम शुरू करवाया था।

निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट मिक्सर मशीन को दूसरी जगह ले जाने की जरूरत पड़ी। घायल गिदाराम सैनी के अनुसार, मशीन को सभी लोग मिलकर धक्का देकर आगे ले जा रहे थे। इसी दौरान मशीन ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवी की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। मशीन में करंट दौड़ते ही आसपास मौजूद मजदूर और ग्रामीण इसकी चपेट में आ गए। हादसे में आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए।

ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बिजली के पोल और लाइन पेड़ों के संपर्क में हैं। लाइन बंद कराने के लिए फोन किया गया, लेकिन ग्रिड सबस्टेशन (जीएसएस) पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। हाईटेंशन लाइन का तार रोड़ी-बजरी मिक्सर मशीन के हाइड्रोलिक जैक के संपर्क में आ गया। इससे मशीन में करंट फैल गया और वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। छापोली निवासी प्रमोद सैनी ने मांग की कि मृतकों के आश्रितों को संविदा पर नौकरी दी जाए और प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि इसके बाद गांव की कमेटी जो निर्णय करेगी, उसी के अनुसार मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों के धरने और हंगामे के बाद उदयपुरवाटी थाने की पुलिस के साथ आरएसी के जवानों को भी गांव में तैनात किया गया है। घायल गिदाराम सैनी ने बताया कि छापोली में वे सभी काम कर रहे थे। मशीन को धक्का देकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इसी दौरान मशीन ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आ गई और करंट फैल गया। हादसे के समय मौके पर 12-13 लोग मौजूद थे।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा- मृतकों के आश्रितों को अलग-अलग योजनाओं में 15 लाख मुआवजा और एक-एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बनी है।

विकास अधिकारी और तहसीलदार को राजस्थान और केंद्र सरकार की योजनाओं में लाभ देने के लिए कहा है। वन विभाग की जमीन पर बन रहे इस रास्ते को लेकर झुंझुनूं के डीएफओ को निर्देश दिए है कि संबंधित जनप्रतिनिधि से संपर्क कर रास्ते के डायवर्जन के प्रस्ताव को पोर्टल पर अपलोड करें। बातचीत के बाद परिजन शव लेने को तैयार हो गए और धरना खत्म कर दिया।

मुख्यमंत्री ने छापोली हादसे पर जताया गहरा दुख, घायलों के त्वरित एवं बेहतर उपचार के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के छापोली गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों के विद्युत लाइन की चपेट में आने से हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला कलक्टर से दूरभाष पर हादसे की विस्तृत एवं तथ्यात्मक जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों के उपचार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाए। साथ ही, घायल श्रमिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि घटना के प्रत्येक पहलू की गंभीरता से जांच की जाए, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता चल सके।

'भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो-2026' का शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने राजस्थान की स्टॉल्स का किया उद्घाटन और अवलोकन



जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो-2026' का उद्घाटन किया। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में 50 प्रतिशत से अधिक विद्युत क्षमता गैर जीवाश्म ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित हो चुकी है, जो कि पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2030 से 5 वर्ष पहले वर्ष 2025 में ही हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर' की भावना के साथ भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी की उपस्थिति में 50 से अधिक प्रमुख निवेशकों के साथ राउंड टेबल बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं एवं उपलब्ध अवसरों को रेखांकित किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। राउंड टेबल बैठक में ब्रुकफील्ड, रिन्यू, आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स, जिंदल समूह और अवाडा सहित अन्य प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। मुख्यमंत्री ने राजस्थान की स्टॉल्स का उद्घाटन और अवलोकन भी किया। इस दौरान ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर एवं मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लगभग 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। इस दिशा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइब्रिड परियोजनाओं एवं ऊर्जा भंडारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति लागू की है। साथ ही, मेगा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'राइट टू यूज' नीति जारी की गई है। वहीं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 51 हजार मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है, जिसमें सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 45 हजार मेगावाट से अधिक है। राज्य में बड़े सौर पार्कों, रूफटॉप सोलर, पवन ऊर्जा, बायोमास एवं ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं, सौर ऊर्जा के अतिरिक्त उत्पादन के उपयोग तथा पीक डिमांड के दौरान ग्रिड प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के विकास की कार्ययोजना तैयार की गई है।

'असली संसद में कभी पीएम नहीं बन पाएंगे राहुल', अमित शाह का तंज

हैदराबाद (एजेंसी)। अमित शाह सोमवार को हैदराबाद में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च में शामिल हुए। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली में नकली संसद लगाई। वे उसके ही पीएम बन जाते तो सोनिया जी के दिल को शांति मिल जाती। असली संसद में वे कभी पीएम नहीं बनेंगे। विपक्ष के स्ट्रक विरोध के जवाब में भाजपा देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान चला रही है। इसका पहला चरण 22 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक चलेगा। कांग्रेस पार्टी एसआईआर को रोककर देश की मतदाता सूची से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है। ये घुसपैठिए उनके वोट बैंक हैं। राहुल जी जितना जोर लगाना है लगा लो, भाजपा एक-एक घुसपैठिए को देश और वोटर्स लिस्ट से बाहर निकालकर दम लेगी। 3 करोड़ वोट बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। राहुल जी कहते हैं कि हम (भाजपा) एसआईआर से जीते। जरा बताओ क्या 2014 में एसआईआर हुआ था। 2019 में जीते, तब भी एसआईआर नहीं हुआ था। 2024 में भी जीते, उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, बंगाल, असम जीते। अब तेलंगाना भी जीतने वाले हैं। राहुल जी, दो दिन पहले आपने मॉक पार्लियामेंट की थी, अगर मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि ये नकली संसद में आप एक बार पीएम बन जाओ, क्योंकि असली संसद में वे कभी बन नहीं पाएंगे, ताकि सोनिया जी के दिल को शांति मिल जाए। राहुल जी चुनाव होते ही आप विदेश चले जाते हैं। देश में पसीना बहाना पड़ता है। हाथ में संविधान रखते हैं, लेकिन उसका सम्मान नहीं करते। ईवीएम, एसआईआर, घुसपैठिए के मुद्दे पर हम संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए आ जाइए, लेकिन वे नहीं आएंगे। वे अराजकता से खुद को सुर्खियों में रखते हैं। जब भी चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं ईवीएम के कारण जीते। राहुल जी, अगर ईवीएम खराब है तो रेवंत रेड्डी कैसे सीएम बन गए, केरल में आपकी सरकार कैसे आई, हिमाचल में कैसे आई।



दीपावली पर जयपुर मेट्रो की सौगात, रात 12:30 बजे तक दौड़ेंगी ट्रेनें



जयपुर (कासं)। जयपुर मेट्रो राष्ट्रीय पर्वों, त्यौहारों एवं उत्सवों के दिनो में भी जनता के प्रति अपना सामाजिक सरोकार पूरी तरह निभाता रहा है। इसी कड़ी में आगामी दीपावली सीजन पर दिनांक 03.11.2026 से 11.11.2026 तक जयपुर मेट्रो ट्रेन के फेरों की संख्या वर्तमान संख्या 202 से बढ़ाकर 214 कर दी गई हैं।

दीपावली को लेकर परकोटे के मुख्य बाजारों में रोशनी की सजावट को देखने एवं खरीददारी हेतु काफी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक एवं शहरवासियों के आगमन को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया हैं। शहर में दिनांक 06.11.2026 से 09.11.2026 तक यातायात के सुगम संचालन हेतु परकोटा क्षेत्र में चलने वाले सिटी/मिनी बसों, ऑटो एवं ई-रिक्शा इत्यादि का प्रवेश भी वर्जित रहेगा।

अत: जयपुर मेट्रो प्रशासन द्वारा शहरवासियों की सुविधा हेतु जयपुर मेट्रो के संचालन फेरों की संख्या बढ़ाते हुए अन्तिम मेट्रो ट्रेन का संचालन मानसरोवर एवं बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से रात्रि 12:30 बजे तक किये जाने का भी निर्णय लिया गया हैं।

जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक वैभव गालरिया ने मेट्रो प्रशासन की और से जयपुरवासियों तथा मेट्रो यात्रियों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की और बताया कि मेट्रो यात्री दिनांक 03.11.2026 से 11.11.2026 तक मेट्रो संचालन की इस व्यवस्था का लाभ उठा पाएंगे।

पंचायत चुनाव का रण तैयार, 442 बूथों पर आज होगा मतदान

जयपुर (कासं)। पंचायतीराज आम चुनाव के तृतीय चरण के तहत जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों एवं जिला परिषद् के वार्डों में 03 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सोमवार को श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी परिसर से मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण के उपरांत ईवीएम एवं निर्वाचन संबंधी आवश्यक सामग्री के साथ निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। मतदान दलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव सामग्री उपलब्ध कराई गई। सामग्री प्राप्त करने के बाद दल अपने संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। मतदान दलों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गईं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र, सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान दलों एवं मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति एवं सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें। उन्होंने बताया कि तृतीय



चरण के तहत जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों चाकसू, कोटखावदा, माधोराजपुरा, फागी एवं सांगानेर के मतदान दल निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार रवाना हुए। पंचायत समिति क्षेत्र फागी के 90 मतदान दल, माधोराजपुरा के 93, चाकसू के 93, कोटखावदा के 82 तथा सांगानेर के 84 मतदान दल संबंधित चेक पोस्ट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए निर्धारित गंतव्य मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे।

मतदान के पश्चात सभी दल निर्धारित मार्ग से वापस जयपुर लौटेंगे। चाकसू पंचायत समिति के 17 पंचायत समिति वार्ड और 32 ग्राम पंचायतों के लिए 93 मतदान केंद्र, कोटखावदा के 15 पंचायत समिति वाड और 27 ग्राम पंचायतों के लिए 82 मतदान केंद्र, माधोराजपुरा के 15 पंचायत समिति वार्ड और 25 ग्राम पंचायतों के लिए 93 मतदान केंद्र, फागी के 15 पंचायत समिति वार्ड और 26 ग्राम पंचायतों के लिए 90 मतदान केंद्र तथा सांगानेर के 15 पंचायत समिति वार्ड और 23 ग्राम पंचायतों के लिए 84 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

दैनिक लोकजीवन
जयपुर एवं भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित
संपादक - स्व. डॉ. विश्वबन्धु जी विश्नोई

डिजिटल क्रांति का भ्रमजाल, शोषण का नया चक्रव्यूह

- ललित शर्मा -

इक्कीसवीं सदी के इस दौर में जिस तकनीकी क्रांति को मानवीय स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम बताकर प्रचारित किया गया, वही आज मानवीय संवेदनाओं, आत्मीय रिश्तों और आत्म-विवेक के क्षरण का कारण बन रही है। स्मार्टफोन और सस्ते डेटा के कॉकटेल ने पूरी मानव आबादी को एक ऐसी अंतहीन और अदृश्य दौड़ में झोंक दिया है जहां हर व्यक्ति निर्माता और उपभोक्ता दोनों बनने के भ्रम में जी रहा है। इस भ्रम में लोग ये भी भूल चुके हैं कि यदि सभी कंटेंट क्रिएटर्स बन जाएंगे तो उसका दर्शक और श्रोता कौन होगा! क्योंकि सभी लोग यहां-वहां से कट-कॉपी करके कुछ भी क्रिएट तो करना चाहते हैं, पर दर्शक नहीं बनना चाहते। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसने आम नागरिक को ही एक उत्पाद में बदल दिया है। क्रिएटर इकोनॉमी का जो सुनहरा सपना दुनिया भर के युवाओं को दिखाया जा रहा है, वह असल में टेक-दिग्गजों द्वारा बुना गया एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह है जिसमें पूंजी का प्रवाह हमेशा ऊपर की ओर होता है। उपकरण बनाने वाली कंपनियां हर साल नए मॉडल पेश कर अरबों का राजस्व जुटाती हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर डेटा प्लान बेचकर अपनी तिजोरियां भरते हैं और एल्गोरिदम नियंत्रित करने वाले प्लेटफॉर्म्स विज्ञापनों से मनमाना मुनाफा कमाते हैं। दूसरी ओर, इस पूरी व्यवस्था की नींव में खड़ा आम इनसान अपनी अमूल्य ऊर्जा, समय, निजता और मानसिक शांति को दांव पर लगाकर दिन-रात वीडियो बनाने में जुटा है। उसे लगता है कि एक दिन उसका कोई वीडियो वायरल होगा और उसकी किस्मत बदल जाएगी। परंतु इस डिजिटल जुए में जीत हमेशा प्लेटफॉर्म्स और पूंजीपतियों की होती है, जबकि आम क्रिएटर केवल उम्मीद के सहारे शोषण का शिकार बनता है। क्रिएटर अर्थव्यवस्था का वास्तविक गणित जितना आकर्षक दिखता है, धरातल पर उसकी स्थिति उतनी ही भयावह और निराशाजनक है। गोल्डमैन सैच्स और प्यू रिसर्च जैसे वैश्विक संस्थानों के आंकड़ों के अनुसार, यूट्यूब पर करोड़ों सक्रिय चैनल मौजूद हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन के मामले में स्थिति बेहद चिंताजनक है। प्लेटफॉर्म के कुल सक्रिय चैनलों में से केवल 4 से 4.3 प्रतिशत चैनल ही 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे के वॉच टाइम की बुनियादी शर्तों को पूरा कर पाते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि 95.7 प्रतिशत से अधिक चैनल विज्ञापनों से एक रुपया भी कमाने की पात्रता हासिल नहीं कर पाते। जो मात्र 4 प्रतिशत चैनल इस यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम (वाईपीपी) में शामिल हो भी जाते हैं, उनमें से भी अधिसंख्य केवल 1500 से 15000 रुपए प्रति माह ही कमा पाते हैं, जो मूलभूत खर्चों के लिए भी अपर्याप्त है। हालांकि कुछ चैनलों की पूर्णकालिक आय 3 लाख रुपए प्रति माह अवश्य है, किंतु ऐसे चैनल कुल सक्रिय क्रिएटर्स का केवल 0.25 प्रतिशत से भी कम (अर्थात प्रति 1000 में सिर्फ 2 या 3) हैं। आय के संदर्भ में विभिन्न मंचों की तुलनापरक स्थिति भी उत्साहवर्द्धक नहीं है।

इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट एड-रेवेन्यू मॉडल अत्यंत सीमित है, जहां 91 प्रतिशत क्रिएटर्स 1 से 10 हजार फॉलोअर्स वाले नैनो-इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्हें कोई नियमित वित्तीय लाभ नहीं मिलता। केवल शीर्ष 5 से 8 प्रतिशत क्रिएटर्स ही ब्रांड स्पॉन्सरशिप, रील्स बोनस या एफिलिएट मार्केटिंग द्वारा धनार्जन कर पाते हैं। टिकटॉक पर भी क्रिएटर फंड का पे-आउट ढांचा प्रति 1000 व्यूज पर बेहद कम (0.40 से 1.00 डॉलर) है, जिससे 10 लाख व्यूज पर मात्र 400 से 1000 डॉलर ही मिल पाते हैं। यहां भी वित्तीय सफलता के लिए सीधे ब्रांड डील्स या लाइव स्ट्रीमिंग का सहारा लेना पड़ता है। सोशल मीडिया मंचों से धनार्जन का झूठ देश-दुनिया के पूरे समाज में इस प्रकार फैला कि दुनिया के 8 अरब 30 करोड़ लोगों में से 5 अरब 9 करोड़ लोग अपने-अपने वीडियो बनाकर ऐसे मंचों पर प्रसारित कर रहे हैं। ऐसा करने की प्रक्रिया में मोबाइल फोन उपकरण बनाने वाली कंपनियां, मोबाइल फोन में लगने वाले छोटे-बड़े कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियां, फोन तथा कलपुर्जों का कच्चा माल उत्खनित, उत्पादित करने वाली कंपनियां, इंटरनेट संचार प्रणाली स्थापित-प्रसारित करने वाली कंपनियां, इन कंपनियों का विज्ञापन करने वाले सेलेब्रिटीज यानी नामी-गिरामी व्यक्ति और अंततः ऐसी कंपनियों को धंधा करने की अनुमति देने वाली विभिन्न देशों की सरकारें तथा उनके बड़े पदों पर बैठे पदाधिकारी तो खूब धनार्जन कर रहे हैं, सुख-सुविधाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दुनिया में उपलब्ध हर प्रकार का ऐश-ओ-आराम भोग रहे हैं, पर लगभग 5 अरब 9 करोड़ लोगों को झांसे, भ्रम और उम्मीद से बांधकर उन्हें वास्तविक जिंदगी में दुःख-दुविधाओं में ही धकेल रहे हैं। ऐसे लोगों में से 5 अरब 1 करोड़ या 3 करोड़ लोगों के पास स्मार्ट फोन हैं। यानी वीडियो बनाने व अपलोड करने में सक्षम फोन। कुल मोबाइल कनेक्शन/सब्सक्रिप्शन की संख्या 9 अरब से अधिक है, क्योंकि कई व्यक्तियों या व्यावसायिक संस्थानों के पास एक से अधिक सिम/मोबाइल कनेक्शन होते हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर अपने-अपने वीडियो बनाकर डालने तथा फिर उनके वायरल होने की उम्मीद में इतने लोगों का अधिकांश समय मोबाइल फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन्स पर आंखें टिकाए हुए व्यतीत हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का दोटूक संदेश, सियासत नहीं संविधान सर्वोपरि

सुप्रीम कोर्ट से स्थिति स्पष्ट होने के बाद इंडिया गठबंधन के दलों के पास अपनी मांगों को लेकर कानूनी प्रक्रिया अपनाने का एक ही रास्ता बचा था, वह था रिट याचिका के जरिए न्याय का तकाजा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च निकाला और रिट याचिका दायर की, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 विपक्षी नेता याचिकाकर्ता हैं। इसमें चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पार्टी बनाया गया है। दरअसल इससे पहले सीजेआई से अकेले ही मुलाकात की मांग करके कांग्रेस ने यह साबित करने की कोशिश की थी, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वही करती है।

देश के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह राजनीतिक दलों की सत्ता को लेकर चल रही मारामारी के बीच अखाड़ा नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कायदे कानून और संविधान के दायरे में रह कर ही काम करेगा। दरअसल यह संदेश सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के जरिए तमाम राजनीतिक दलों को दिया, जोकि सुप्रीम कोर्ट के जरिए राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई गलतफहमी या अफवाह फैले, इससे पहले ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए पत्रकार वार्ता आयोजित की। सीजेआई ने यह कदम इसलिए उठाया कि नेता कहीं बात का बतंगड़ नहीं बना दे और उसमें सुप्रीम कोर्ट को इसमें नहीं घसीट लें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा था कि वे उन्हें एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे जिसमें वोट चोरी रोकने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, मतदाता सूची के एसआईआर को रोकने और पुनः मतपत्र प्रणाली पर लौटने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह मांग यह कहते हुए ठुकरा दी कि यदि सुनवाई चाहते हो तो रिट याचिका दायर करो। सीजेआई ने राहुल गांधी के आधिकारिक ईमेल के जवाब में कहा कि इस तरह की मुलाकात उचित नहीं होगी, क्योंकि जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई है, वे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।

इसी के साथ सीजेआई ने दूरदर्शिता अपनाते हुए अगले ही दिन प्रेस कांफ्रेंस करके स्थिति स्पष्ट कर दी ताकि राजनीतिक दल उसकी बातों का गलत मतलब नहीं निकाल पाएं और सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक विवाद में नहीं घसीट सकें। सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट, प्रशासनिक स्तर पर सरकार के कामकाज में दखल नहीं दे सकता, हालांकि नेताओं को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक पक्ष में अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक दो बार ही ऐसा हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीडिया के जरिए कोई जानकारी दी गई है, वरना तो मीडिया ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और सुनवाई की जानकारी देता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जजों द्वारा मीडिया से सीधे संवाद करने या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे चर्चित मौका 12 जनवरी 2018 को आया था। सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों जस्टिस जे. चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी. लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारतीय न्यायिक इतिहास में यह पहला अवसर था जब वर्तमान जजों ने इस तरह मीडिया को संबोधित किया था। इन जजों ने तब के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ रोस्टर और प्रशासनिक कामकाज को लेकर सार्वजनिक सवाल उठाए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकांश जानकारी और फैसले आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों, अपनी वेबसाइट और सुनवाई के जरिए ही साझा करता है। हाल के दौर में अदालत ने न्यायिक कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीमिंग और उसके डिजिटल क्लिप्स के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर भी कड़े नियम तय किए हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया था कि मुझे कल बैठक के अनुरोध के संबंध में एक पत्र मिला था। मैंने कल रात ही उसका जवाब दे दिया था, जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया गया था कि मैं क्यों नहीं मिल पाऊंगा। सीजेआई ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। किसी भी आम नागरिक या निर्वाचित निकाय के सदस्य की किसी भी याचिका का स्वागत है। हर भारतीय नागरिक को अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। हम उनकी चिंताओं को सुनेंगे और कानून के तहत जो भी उचित होगा, वह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से स्थिति स्पष्ट होने के बाद इंडिया गठबंधन के दलों के पास अपनी मांगों को लेकर कानूनी प्रक्रिया अपनाने का एक ही रास्ता बचा था, वह था रिट याचिका के जरिए न्याय का तकाजा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च निकाला और रिट याचिका दायर की, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 विपक्षी नेता याचिकाकर्ता हैं। इसमें चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पार्टी बनाया गया है। दरअसल इससे पहले सीजेआई से अकेले ही मुलाकात की मांग करके कांग्रेस ने यह साबित करने की कोशिश की थी, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वही करती है।

बाकी सब उसके पीछे हैं, किन्तु सीजेआई द्वारा मिलने से इंकार करने से कांग्रेस को अपने दाव में सफलता नहीं मिल सकी। जब सीजेआई ने मिलने से इंकार कर दिया और कानूनी तरीका अपनाने की सलाह दी, तब गठबंधन के बाकी नेताओं को भी साथ लेकर याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर कर दिया कि गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं के मंसूबे कामयाब नहीं होने देगा। जो भी करेगा संविधान के दायरे में करेगा, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी बट्टा लग सकता है। यह भी निश्चित है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को कोई खास सफलता सुप्रीम कोर्ट से हाथ नहीं लगने वाली, सिवाय एसआईआर में कुछ प्रशासनिक आदेश निर्देश के, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं जा सकता, उन्हें संविधान का संरक्षण प्राप्त है। केवल संसद में महाभियोग के जरिए ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाया जा सकता है, वह इसलिए पूरा नहीं होगा कि संसद में मोदी सरकार का बहुमत है। इससे पहले भी राजनीतिक इरादों को पूरा करने के विपक्षी दलों के मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट पानी फेर चुका है। नवम्बर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने देश में चुनावों में धांधली का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा था कि जब आप चुनाव जीतते हैं, तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती। जब आप चुनाव हार जाते हैं, तो छेड़छाड़ हो जाती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर तीखा व्यंग्य करते हुए पूछा कि ये याचिका दायर करने संबंधित आपको शानदार विचार कैसे मिला? इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में 14 विपक्षी दलों की सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के लिए नेताओं के लिए अलग से गाइडलाइंस बनाने के निर्देश देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के ज्यादा केस दिखाने वाले आंकड़ों के आधार पर केवल नेताओं के लिए गाइडलाइन की मांग नहीं कर सकते हैं। उन्हें अभियोजन से कोई छूट नहीं मिलती है। कोर्ट ने कहा कि नेता आम नागरिकों के बराबर ही होते हैं। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। राजनीतिक दलों के मामले में दूरी बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से साफ है कि इंडिया गठबंधन को अपने राजनीतिक मुद्दों की लड़ाई जनता की अदालत में लडनी होगी।

युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर परिवार और संस्थानों को देना होगा विशेष ध्यान

भारत में आत्महत्या के आंकड़े केवल संख्याओं का बढ़ता हुआ ग्राफ नहीं हैं, बल्कि वे हमारे समाज के भीतर बढ़ते मानसिक दबाव, अकेलेपन, आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक तनाव और भावनात्मक संवाद की कमी की गंभीर तस्वीर भी सामने रखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट 'एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया-2024' के अनुसार वर्ष 2024 में देश में 170746 आत्महत्याएं दर्ज की गईं। यानी औसतन प्रतिदिन 468 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह आंकड़ा इसलिए भी चिंता पैदा करता है क्योंकि इसके पीछे केवल व्यक्तिगत परिस्थितियां नहीं, बल्कि परिवार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों से जुड़ी अनेक परतें दिखाई देती हैं। इस समस्या का सबसे संवेदनशील पक्ष युवाओं और विद्यार्थियों से जुड़ा है। 29 सितंबर 2026 को सामने आए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के प्रारंभिक निष्कर्षों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

दो लाख 43 हजार से अधिक विद्यार्थियों के जवाबों पर आधारित इस सर्वेक्षण में करीब 15 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि पिछले छह महीनों में वे कई सप्ताह तक अत्यधिक तनाव, परेशानी, उदासी या बेचैनी की स्थिति से गुजरे, जबकि करीब 9 प्रतिशत ने पिछले एक वर्ष में अक्सर या बहुत बार आत्महत्या के विचार आने की बात कही।

लगभग 34 प्रतिशत विद्यार्थियों ने किसी न किसी स्तर पर परिसर में खुद को बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस किया। करीब 32 प्रतिशत ने यह भी बताया कि उनके संस्थान में काउंसिलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय कार्यबल ने अपने अध्ययन में सामाजिक भेदभाव, परिसर में अलगाव की भावना, अकादमिक दबाव और संस्थागत सहायता की कमी जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया है। हालांकि इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष अभी प्रारंभिक हैं और इसे पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि तस्वीर नहीं माना जा सकता, फिर भी इतने बड़े सर्वेक्षण में सामने आए संकेतों को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। आत्महत्या को केवल मानसिक बीमारी का परिणाम मानना भी सही नहीं होगा। वर्ष 2024 के एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार बीमारी से जुड़ी 30617 आत्महत्याएं दर्ज हुईं। इनमें 14305 मामले मानसिक बीमारी से संबंधित थे, जो बीमारी के कारण हुई आत्महत्याओं का लगभग



47 प्रतिशत है। डाउन टू अर्थ और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के विश्लेषण के अनुसार 2023 में मानसिक बीमारी से जुड़ी ऐसी मौतों की संख्या 13978 थी। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानसिक बीमारी, बीमारी-संबंधी आत्महत्याओं का प्रमुख कारण रही। हिमाचल प्रदेश भी इस चिंता से अछूता नहीं है। हिमाचल पुलिस के क्राइम रिव्यू-2024 के अनुसार प्रदेश में 2024 में 813 आत्महत्याएं दर्ज हुईं।

इनमें 564 पुरुष और 249 महिलाएं थीं। अकेले कांगड़ा जिले में 137 मामले दर्ज हुए, जो प्रदेश के जिलों में उल्लेखनीय संख्या है। यह आंकड़ा हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि पहाड़ की शांत दिखाई देने वाली जिंदगी के भीतर भी कितने लोग ऐसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिसे वे किसी से कह नहीं पाते। इस स्थिति में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

किसी परेशान व्यक्ति को तुरंत उपदेश देने के बजाय उसकी बात सुनना, उसके अनुभव को गंभीरता से लेना और जरूरत पडने पर विशेषज्ञ तक पहुंचाना जरूरी है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में केवल करियर काउंसलिंग नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सहायता की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों को भी ऐसे संकेत पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार विद्यार्थी अपने माता-पिता से पहले अपने शिक्षक के सामने अपनी परेशानी व्यक्त करता है। बढ़ती आत्महत्याओं और आत्मघाती विचारों का मुख्य इलाज पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सहायता, मनोचिकित्सा थेरैपी और उचित दवाओं का संयोजन है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, टेली मानस के माध्यम से 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध है।

इसके लिए 14416 या 1800.89.14416 पर संपर्क किया जा सकता है। सेवा का उद्देश्य केवल फोन पर बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पडने पर आगे की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोडना भी है। आत्महत्या की रोकथाम का अर्थ केवल संकट के समय किसी व्यक्ति को बचाना नहीं, बल्कि ऐसी सामाजिक परिस्थितियां बनाना भी है जहां व्यक्ति अपनी परेशानी समय रहते साझा कर सके।

हमें बच्चों को यह सिखाना होगा कि असफलता अंत नहीं है, युवाओं को यह भरोसा देना होगा कि रोजगार या परीक्षा में असफलता उनकी पूरी पहचान नहीं है और परिवारों को यह समझना होगा कि भावनाओं पर बातचीत कमजोरी नहीं, बल्कि संबंधों की मजबूती है। मीडिया की भूमिका भी अत्यंत संवेदनशील है। आत्महत्या की घटनाओं को सनसनी, रोमांच या विस्तृत विवरण के साथ प्रस्तुत करने के बजाय उसके सामाजिक संदर्भ, चेतावनी संकेतों, सहायता सेवाओं और रोकथाम के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु को खबर बनाना आसान है, लेकिन समाज में यह भरोसा पैदा करना कहीं अधिक जरूरी है कि संकट की घड़ी में मदद उपलब्ध है। आंकड़े हमें चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन आंकड़े अकेले किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते।

जिंदगी तब बचती है जब कोई समय पर पूछता है- 'तुम ठीक हो?' और जवाब सुनने के लिए सचमुच रुकता भी है। आत्महत्या रोकने की शुरुआत बड़े सरकारी कार्यक्रमों से जितनी होती है, उतनी ही एक संवेदनशील परिवार, एक समझदार शिक्षक, एक सजग मित्र और एक ऐसे समाज से भी होती है जहां परेशानी छिपाने के बजाय साझा करने को साहस माना जाए। हमें आत्महत्या के आंकड़ों को केवल बढ़ती संख्या के रूप में नहीं, बल्कि हर संख्या के पीछे मौजूद एक अधूरी जिंदगी, एक परिवार की पीड़ा और एक ऐसी संभावना के रूप में देखना होगा जिसे समय पर सहायता देकर बचाया जा सकता है।

अमेरिकी विकेंद्रीकृत चुनाव प्रणाली से सबक लेने की जरूरत

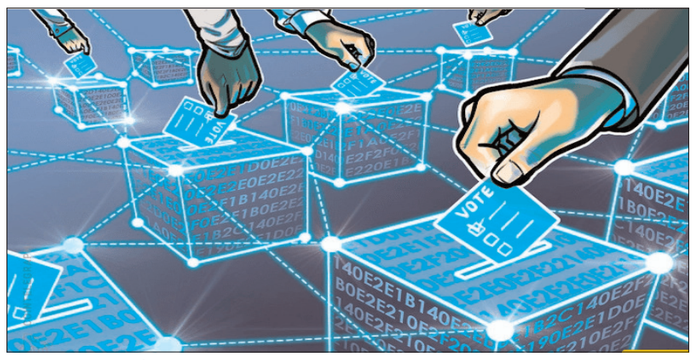
मतदाता सूची प्रबंधन और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता जरूरी

संयुक्त राज्य अमेरिका इसके विपरीत एक अलग मॉडल प्रस्तुत करता है। वहां राज्य और स्थानीय प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण संबंधी रिकॉर्ड का रखरखाव करते हैं और संघीय चुनावों सहित सभी चुनावों का संचालन करते हैं। यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था चुनावों के प्रशासन को किसी एक संस्था के हाथों में केंद्रित होने से रोकती है। साथ ही, यह व्यावहारिक वास्तविकता को स्वीकार करती है कि चुनावों का संचालन अंततः स्थानीय स्तर पर ही होना है और स्थानीय प्राधिकरण इसके लिए अधिक सक्षम स्थिति में होते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिकी राज्य अपनी मनमानी कर सकते हैं। उन्हें संघीय चुनाव कानूनों का पालन करना पड़ता है। इनमें 1965 का वोटिंग राइट्स एक्ट, 1984 का वोटिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर दि एल्डरली एंड हैंडीकैप्ड एक्ट और 1993 का नेशनल वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट शामिल हैं। ये कानून मतदान के अधिकारों की रक्षा करते हैं, भेदभाव पर रोक लगाते हैं, मतदाता पंजीकरण और मतदाता पहचान-पत्रों से संबंधित आवश्यकताएं निर्धारित करते हैं तथा मतदान केंद्रों तक पहुंच के लिए सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराते हैं। चुनावी चंदे और अभियान वित्त को नियंत्रित करने के लिए भी अलग कानून हैं। हाल के वर्षों में अमेरिका में भी मतदाता सूचियां राज्य सरकारों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बीच बड़े राजनीतिक टकराव का विषय बनी हैं। मई 2025 से ट्रंप प्रशासन ने राज्यों के मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड तक पहुंच की मांग की है। उसका तर्क है कि संघीय कानून उसे रिकॉर्ड की शुद्धता की जांच के लिए उनका निरीक्षण करने का अधिकार देता है। कई राज्यों ने इसका विरोध किया और केंद्र सरकार के कानूनी अधिकार पर सवाल उठाए। इसके परिणामस्वरूप 30 से अधिक मुकदमे दायर हुए, जिनमें से अधिकांश को अदालतों ने खारिज कर दिया।

भारत के विपक्ष के लिए इससे यह सबक मिलता है कि मतदाता सूची के प्रबंधन को एकमात्र राष्ट्रीय प्राधिकरण के हाथों में रखना जरूरी नहीं है। उसे ऐसे कानून की मांग करनी चाहिए, जिसके तहत मतदाता सूचियों के रखरखाव और उन्हें अद्यतन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी जाए, जबकि निर्वाचन आयोग को नियमित और स्वतंत्र ऑडिट कराने का अधिकार प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था अचानक बड़े पैमाने पर और व्यवधान पैदा करने वाले पुनरीक्षण अभियानों की आवश्यकता को कम कर सकती है।

विपक्ष को एसआईआर को लेकर जनता में पैदा हुए असंतोष का इस्तेमाल इस



बुनियादी सुधार के लिए दबाव बनाने में करना चाहिए। अन्यथा, एसआईआर को पूरी तरह रोकने की उसकी मांग का ठोस कानूनी आधार कमजोर दिखाई देता है। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण एक वैध जिम्मेदारी है, वास्तविक सवाल यह है कि प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और पर्याप्त सुरक्षा उपायों से युक्त है या नहीं। पुनरीक्षण को पूरी तरह रोकने की मांग उतनी ही मनमानी प्रतीत होती है, जितने मनमाने फैसलों का आरोप विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर लगा रहा है। दूसरी बुनियादी समस्या उन अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ी है, जो चुनावों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। कई दशकों तक नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रही, क्योंकि संसद ने लंबे समय तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया था, जो स्वतंत्र चयन तंत्र निर्धारित करता। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जब तक संसद ऐसा कानून नहीं बनाती, तब तक नियुक्तियों की सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद संसद ने एक नया कानून बनाया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को शामिल किया गया। अब चयन समिति में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित एक मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। इस प्रकार सरकार के पास समिति के तीन में से दो सदस्यों का समर्थन होता है। यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से हितों के टकराव की स्थिति पैदा करती है। इससे निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को लेकर विश्वास कमजोर होता है, भले ही नियुक्त किया गया कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से निष्पक्ष तरीके से काम करे।

2023 का यह कानून विपक्ष के कड़े विरोध के बीच पारित हुआ था। सरकार ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया, जहां विपक्षी सदस्यों के सदन से बहिर्गमन के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके कुछ दिन बाद लोकसभा ने भी इसे पारित कर दिया।

उस समय संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़े पैमाने पर विपक्षी सांसदों के निलंबन के कारण अधिकांश विपक्षी सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। उस शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों के कुल 146 विपक्षी सांसद निलंबित किए गए थे। अब विपक्ष को वास्तव में स्वतंत्र चयन तंत्र की मांग करनी चाहिए, जिसमें सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधियों के साथ-साथ न्यायपालिका और अन्य विश्वसनीय संवैधानिक या सार्वजनिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हों। प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी एक राजनीतिक दल को परिणाम तय करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए।

भारत के लोकतंत्र की रक्षा केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाकर दूसरे को नियुक्त करने या हर विवादास्पद चुनावी फैसले को एक अलग राजनीतिक लड़ाई के रूप में चुनौती देने से नहीं हो सकती। विपक्ष को दो परस्पर पूरक सुधारों के लिए अभियान चलाना चाहिए। पहला, मतदाता सूचियों के रखरखाव और अद्यतन की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जाए, जबकि राष्ट्रीय मानक और निगरानी की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास रहे। दूसरा, निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार के निर्णायक प्रभाव को समाप्त किया जाए। असल सुधार किसी एक अधिकारी को बदलने में नहीं, बल्कि उस संस्थागत व्यवस्था को बदलने में है जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) को लेकर चल रहा विरोध गलत मुद्दों पर केंद्रित है। विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार सत्तारूढ़ दल का पक्ष ले रहे हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्तों के विचारों की अनदेखी कर रहे हैं और मनमाने ढंग से मतदाता सूची से लोगों के नाम हटा रहे हैं।

इन चिंताओं की जांच की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष का आंदोलन दो बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटका रहा है। पहला, भारत का संविधान निर्वाचन आयोग को चुनावों के संबंध में व्यापक एकछत्र अधिकार देता है। दूसरा, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून शीर्ष अधिकारियों के चयन में केंद्र सरकार को निर्णायक अधिकार प्रदान करता है।

यदि आलोचक वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, तो उन्हें एसआईआर और सीईसी को अलग-अलग समस्याओं के रूप में देखने के बजाय निर्वाचन आयोग से संबंधित कानूनों में बुनियादी सुधार की मांग करनी चाहिए। समस्या केवल यह नहीं है कि पद पर कौन बैठा है या किसी विशेष चुनावी प्रक्रिया को किस तरह संचालित किया जा रहा है। असली समस्या संस्थागत ढांचे में है, जो पूरी व्यवस्था को दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील बनाता है।

संविधान का अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग को देता है। इतनी व्यापक शक्तियों का एक ही संस्था में केंद्रीकरण न तो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है और न ही भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए व्यावहारिक।

सिर्फ जीभ का जायका ही नहीं, त्वचा को भी खूबसूरत बनाती है चॉकलेट

चॉकलेट खाना न केवल आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, बल्कि इसे त्वचा, चेहरे या शरीर पर लगाने से रंग-रूप भी निखरता है और त्वचा मुलायम हो जाती है।



* चॉकलेट एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो बढ़ती उम्र के लक्षणों को दूर कर त्वचा को जवां और खूबसूरत बनाता है। त्वचा में कसाव लाता है।
* यह एंटी-इनफ्लैमेटरी होता है, जिससे यह रूखी और संवेदनशील त्वचा के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है।
* डार्क चॉकलेट त्वचा में निखार लाने के साथ ही उसे मुलायम बनाता है और त्वचा में नमी बरकरार रखता है।
* चॉकलेट फ्लैवेनोल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखता है, झुर्रियां दूर करता है और त्वचा को नमी प्रदान करता है।
* चॉकलेट में पाया जाने वाला फ्लैवेनोल रक्त चाप को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर त्वचा को कोमल बनाता है।
* चॉकलेट फेशियल आजकल खूब चलन में हैं। यह न सिर्फ त्वचा का रंग साफ करता है, बल्कि झुर्रियां और महीन रेखाएं भी कम करता है।
* एक-तिहाई कप कोको पाउडर में 2-3 बड़ा चम्मच शहद और कुछ नींबू के रस की बूंदे मिलाएं। इस चॉकलेट फेस पैक को चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट छोड़ दें और फिर चेहरा धुलें। इससे त्वचा मुलायम होगी, रंग साफ होगा और चेहरे पर चमक व निखार भी आएगा।
* यह चेहरे पर बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करता है और झुर्रियों, दाग-धब्बों को दूर करता है।

घुटने के दर्द की छुट्टी करेंगे ये 10 दमदार उपाय



अगर आपके घुटने में दर्द होता है तो ये उपाय आपके काफी हद तक राहत दिला सकते हैं। आइए जानें कौन से हैं ये उपाय-

1. कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर बनाए पैड से सिंकाई करने से घुटने के दर्द में आराम मिलता है।
2. भोजन में दालचीनी, जीरा, अदरक और हल्दी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। गर्म तासीर वाले इन पदार्थों के सेवन से घुटनों की सूजन और दर्द कम होता है।
3. मेथी दाना, सौंठ और हल्दी बराबर मात्रा में मिला कर तवे या कढ़ाई में भून कर पीस लें। रोजाना एक चम्मच चूर्ण सुबह-शाम भोजन करने के बाद गर्म पानी के साथ लें।
4. रोज सुबह खाली पेट एक चम्मच मेथी के पिसे दानों में एक ग्राम कलौंजी मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लें। दोपहर और रात में खाना खाने के बाद आधा-आधा चम्मच लेने से जोड़ मजबूत होंगे और किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा।
5. सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली दही के साथ खाएं।
6. हल्दी चूर्ण, गुड़, मेथी दाना पाउडर और पानी सामान मात्रा में मिलाएं। थोड़ा गर्म करके इनका लेप रात को घुटनों पर लगाएं और पट्टी बांधकर लेटें।
7. अलसी के दानों के साथ दो अखरोट की गिरी सेवन करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है।
8. बराबर मात्रा में नीम और अरंडी के तेल को हल्का गर्म करके सुबह-शाम जोड़ों पर मालिश करें।
9. मालिश के लिए आप इन चीजों से भी तेल बना सकते हैं। 50 ग्राम लहसुन, 25 ग्राम अजवायन और10 ग्राम लौंग 200 ग्राम सरसों के तेल में पका कर जला दें। ठंडा होने पर कांच की बोतल में छान कर रख लें। इस तेल से घुटनों या जोड़ों की मालिश करें।
10. गेहूं के दाने के आकार का चूना दही या दूध में घोलकर दिन में एक बार खाएं। इसे 90 दिन तक लेने से कैल्शियम की कमी दूर होगी।

8 ऐसी बातें, जो मां को बनाती है दुनिया की बेस्ट मॉम

ह र मां अपना बच्चा दुनिया मे सबसे प्यारा होता है। मां-बच्चे में भावनात्मक रिश्ता बचपन से ही जुड़ जाता है। अगर पापा की डांस से बचना हो तो मां पूरी मदद करती है। बच्चा दुखी हो तो मां उसके दुख को बांटती है। इसलिए तो वह दुनिया की सबसे बैस्ट मां होती है। आज हम आपको ऐसी ही बातों के बारे में बताएंगे, जो मां को बैस्ट बनाती है।

आपकी पहली टीचर



बच्चे की पहली टीचर होती है मां। क्योंकि बचपन में बच्चा जो कुछ भी सिखता है, वह सब कुछ अपनी मां से सिखता है, जैसे पोयम से लेकर हैंड वॉश करना है। यह सब उसे मां ही सिखाती है।

खाने को लेकर चिंता

अरे, अपना टिफिन बॉक्स पूरा क्यों नहीं खाया? आज भूख क्यों नहीं लगी तुम्हें? मां बच्चे से रोज यहीं बात पूछती है। इन्हीं बातों से पता चलता है। मां को बच्चे की कितनी चिंता होती है।

पापा का गुस्सा ? मम्मी बचाओ!



मां बच्चे को बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचाती हैं। फिर वह मुसीबत कोई और हो या पापा का गुस्सा। पापा की डांस से मम्मी ही बचाती है।

ब्रेकअप के बाद...!!

अगर ब्रेकअप हो जाए तो मां दिलासा देती कहती है। अरे अरे वो तेरे लायक ही नहीं था, मैं तेरे लिए इससे अच्छी लड़की ढूंढ लाऊगी मेरे लाल!

एक्जाम मेरा! मां को चिंता



एक्जाम अगर बच्चे का हो तो चिंता मां को लगी रहती है। रात को बच्चे के साथ बैठ कर गुजार देती है। बीच-बीच में बच्चे को गर्मागर्म कॉफी बना कर देती है।

आपके फ्रैंड्स मां के फ्रैंड्स

अगर कभी-कभार बच्चे के फ्रैंड्स घर पर आ जाए तो मां भी उनको पूर प्यार देती है। अपने बच्चे की तरह उनका भी ख्याल रखती है। उनके साथ अपने ही बच्चे की मजाक-मस्ती करती है। बस यहीं बातें मां को बच्चे की करीब ला देती है।

आप बीमार, मम्मी परेशान



अगर बच्चा परेशान या बीमार होता है तो सबसे ज्यादा इस तकलीफ का अहसास मां को होता है। ऐसे में मां अपने सारे काम छोड़कर आपके सिरहाने बैठ जाती है। आपके सेहतमंद होने की दुआए करती है।

आपका करियर उनका ख्वाब

आपका ख्वाब भी मां का ख्वाब बन जाता है। वह आपके करियर को लेकर काफी चिंता करती है। आपके हर वो सलहा देना चाहती है, जिनसे आपको थोड़ी-बहुत मदद मिल सकें।

स्मार्टफोन पर देर रात यारी आंखों पर पड़ेगी भारी

कभी चैटिंग, कभी गेमिंग तो कभी विडियो कॉलिंग। स्मार्टफोन पर हमारी निर्भरता इस कदर बढ़ी है कि बिना इसके इस्तेमाल के न तो दिन गुजरता है और न रात में नींद आती है। हालांकि, देर रात तक लाइट बंद कर मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाना आंखों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इससे न सिर्फ ड्राई आइज की समस्या होती है बल्कि लोगों की आंखें कमजोर भी हो रही हैं। डॉक्टर्स की मानें तो हर दिन ओपीडी में 20 प्रतिशत मरीज इस तरह की शिकायत लेकर आते हैं। आगे की तस्वीरों में जानें, मोबाइल पर लंबा वक्त बिताने की यह आदत किस तरह सभी उम्र के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है...



मोबाइल से बढ़ रही आइज ड्राइनेस

लोकबंधु अस्पताल की डॉ स्नेहलता कहती हैं एक वक्त के बाद आंखें थक जाती हैं लेकिन हम फिर भी थकी हुई आंखों से काम लेते रहते हैं। यही असली दिक्कत है। रात में मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त जब लाइट्स भी बंद कर दी जाती हैं तो स्क्रीन से निकलने वाली किरणें सीधे आंखों पर पड़ती हैं जिससे वे प्रभावी ढंग से काम करना बंद कर देती हैं। डॉ स्नेहलता कहती हैं कि उनके पास हर ओपीडी में 20 से 30 ऐसे मरीज आते हैं, जो आइज ड्राइनेस का शिकार होते हैं या फिर देर रात तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की वजह से आंखों में दर्द से लेकर कम दिखने की शिकायत करते हैं। आइज ड्राइनेस के लिए एसी भी कुछ हद तक जिम्मेदार होता है।

मोबाइल की वजह से आंखों में प्रॉब्लम आम वजह

यंगस्टर्स अक्सर देर रात तक फॉल्टी पोजीशन (लेटना या गलत ढंग से बैठना) में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। अंधेरे कमरे में स्मार्टफोन की स्क्रीन पर टकटकी लगाए रखने की वजह से अक्सर उन्हें आंखों में इचिंग, ड्राईआइज और आंखें लाल होने की समस्या होती है। ओपीडी में आने वाले इस तरह के पेशंट्स में ज्यादातर 20 से 40 साल की उम्र के होते हैं। मोबाइल का प्रभाव बढ़ते बच्चों पर ज्यादा होता है, जिससे आईसाइट कमजोर होती है। ऐसे पेशंट्स को खासतौर पर फोन का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी जाती है।

मोबाइल चैटिंग की बात छिपाते हैं पेशंट्स

डॉ उमेश कुमार सोनकर कहते हैं कि बच्चे ही नहीं बड़े भी मोबाइल पर घंटों वक्त बिताते हैं। अक्सर रात में लाइट्स बंदकर चैटिंग या विडियो देखने की आदत आंखों पर बुरा असर डालती है। जब लोग हमारे पास कम दिखने जैसी शिकायत लेकर आते हैं तो हम उनका शेड्यूल पूछते हैं। ऐसे में अक्सर लोग मोबाइल पर लंबा वक्त बिताने की बात छिपाते हैं। वे यह नहीं बताना चाहते कि वे देर रात तक मोबाइल पर चैट करते हैं। इसकी बजाय वे दूसरे कारण गिनाने लगते हैं।

चश्मे की बजाए आईड्रॉप का इस्तेमाल

डॉक्टर सोनकर कहते हैं कि इस तरह के मरीजों को वह चश्मा लगाने की सलाह देने के बजाय आईड्रॉप की मदद से ठीक करने पर जोर देते हैं। इस तरह के केस में पेशंट्स 15 दिन से लेकर एक महीने में नॉर्मल आईसाइट के लेवल पर आ जाते हैं। हालांकि, इस तरह के पेशंट्स को डॉक्टर्स चेतावनी देते हैं कि अगर वक्त रहते वे अपनी आदत (लाइट बंद कर मोबाइल पर चैटिंग) पर काबू नहीं पाते हैं तो उनके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है।



बीमारियों बचना है तो हर दिन करें नींबू का सेवन

गर्मी में एक नींबू का सेवन जरूर करना चाहिए। आयुर्वेद के जानकार डॉ. कृष्णा सिंह की माने तो धूप और गर्मी की वजह से शरीर से निकलने वाले पसीने की मात्रा को यह संतुलित रखता है। इसलिए खाली पेट में और खाने में एक नींबू का उपयोग जरूर करना चाहिए।



- यह शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित रखता है
- गर्मियों में होने वाली त्वचा संबंधी बीमारी से भी बचाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
- गर्मी में पेट का इंफेक्शन काफी होता है। ऐसे में नींबू में पाए जाने वाला एंजाइम पेक्टिव फाइबर पेट संबंधी बीमारी को दूर करता है।
- पसीना अधिक निकलने से चक्कर आना, घबराहट और थकान बड़ी समस्या बनी रहती है। नींबू इन समस्याओं से बचाता है।
- पेशाब की समस्या भी गर्मी में बढ़ जाती है। ऐसे में नींबू का पानी पेशाब संबंधी बीमारी को दूर करने में मददगार साबित होता है।
- सब्जी के इस्तेमाल से पहले अगर उसमें नींबू मिलाते है तो उसमें पाया जाने वाला पेस्टीसाइड का असर भी कम हो जाता है।

ताकि आम न पहुंचाएं आपकी सेहत को नुकसान...



हम सभी ने बचपन में सीखा है- चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती! तो इस सबक को आम खरीदते समय भी अपनाएं! गलत तरीके से पकाए गए फल अपना स्वाद, खुशबू, और पोषण खो देते हैं। आम खाने का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि अधपके या कच्चे आम को खरीदा जाए और इसे घर में प्राकृतिक तरीकों से पकाया जाए। सबसे आसान तरीका बेहतरीन आम जांचने का यह है कि आम के उपरी हिस्से को ठीक तरीके से परखा जाए। यह थोडा फूला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आप जिस भी आम का चयन करते हैं वो कीट से मुक्त, ओलों से चोटिल, कटा-फटा नहीं होना चाहिए। खरीदते समय इसकी चमकदार त्वचा पर न जाएं बल्कि इसकी खुशबु और बाहरी रूप-रंग से पहचानने की कोशिश करें।

खाने के तुरंत बाद चाय पीना है बीमारियों को न्यौता देना



लोग अक्सर खाने के बाद चाय पीना पसंद करते हैं। कई लोग सुबह के नाश्ते और रात के डिनर के बाद चाय पीते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने खानपान की जो गाइडलाइन जारी की उसमें इस आदत को छोड़ने की सलाह दी गई है।

एक घंटे के भीतर चाय या कॉफी लेने से बचे

गाइडलाइन में कहा गया है कि सुबह के नाश्ते के एक घंटे के भीतर चाय या कॉफी को पीना बिमारियों का बुलावा बन सकता है। इससे शरीर में आयरन की अवशोषण की क्षमता घटती है और पोषण के बावजूद व्यक्ति एनिमिया (खून की कमी) का शिकार हो जाता है।

खाने के साथ चाय और कॉफी को कहें 'ना'

पोषण से जुड़ा मसौदा आहार मार्गदर्शक समिति के संयोजक डॉ.डी रघुनाथ राव ने कहा कि नाश्ते या भोजन के एक घंटे तक चाय या कॉफी से दूर ही रहना चाहिए। इससे नाश्ते या भोजन में लिए गए आहार का संपूर्ण पोषण शरीर को मिल सकेगा और बीमारियों से भी बचा जा सकेगा।

दिल के मरीज कॉफी से रहे दूर

गाइडलाइन मुताबिक दिल से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों को कॉफी से बचना चाहिए या बहुत कम लेना चाहिए। कॉफी पीने के बाद शरीर में रक्तचाप बढ़ता है जो हृदय की धड़कन को अनियमित बनाता है।

चाय पीने से हो सकती हैं ये बीमारियां

1. चाय में कैफीन की मौजूदगी शरीर में कॉर्टिसोल मतलब स्टेरॉयड हार्मोंस को बढ़ाती है, जिससे शरीर को प्रॉबलम का सामना करना पड़ता है। इनमें दिल से जुड़ी प्रॉबलम, डायबिटीज और वजन बढ़ना शामिल है।
2. चाय की पत्ती में अम्लीय गुण होते हैं जो कि भोजन के प्रोटीन के साथ मिलकर उसे सख्त बना देते हैं। इससे प्रोटीन को पचाने में मुश्किल होती है और पाचन पर असर पड़ता है।
3. चाय या कॉफी में 'टैनिन' केमिकल होता है, जो आयरन के अवशोषण को बाधित करता है। इससे मानसिक और शारीरिक थकान लगती है। जिन महिलाओं को आयरन, कैल्शियम की कमी होती है, उन्हें खाने के बाद चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए।

उदार लोग जीते हैं ज्यादा खुशहाल जीवन



उदारता लोगों को ज्यादा खुशहाल बनाती है, जी हां ये कहना है उन वैज्ञानकों का जिन्होंने अपने शोध में पाया है कि ज्यादा उदार होने से हमारे मस्तिष्क में बदलाव होता है जो हमें सुखद अनुभूति कराता है।शोधकर्ताओं का कहना है कि जो अपने समाज के अन्य लोगों का ख्याल रखते हैं वह उन लोगों से ज्यादा खुश होते हैं जो सिर्फ अपनी जरुरतों की परवाह करते है और केवल अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से असीम आनंद की अनुभूति होती है।

स्विट्जरलैंड स्थित 'यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख' के शोधकर्ताओं ने जांच की कि कैसे लोगों का मस्तिष्क इस भावना को संचारित करती है। शोधकर्ताओं ने अपने शोध में पाया कि जो लोग दूसरों के साथ उदारता से पेश आते हैं वे उन लोगों की तुलना में ज्यादा खुश होते हैं जो स्वार्थपूर्ण तरीके से व्यवहार करते है। शोधकर्ताओं ने बताया कि हालांकि, उदारता का यह पैमाना संतुष्टि में वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है।

'यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख' के फिलिप टॉबलर ने कहा, ''आपको खुशी पाने के लिए आत्म-त्याग की आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़ा अधिक उदार बनना पड़ेगा।'' इस प्रयोग में भाग लेने वाले लोगों को दूसरों से ज्यादा उदारता से व्यवहार करने के लिए कहा गया, जिसमें पाया गया कि ये लोग अन्य से बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''उदारपूर्वक व्यवहार से आप समाज में अभीष्ट व्यवहार को सुदृढ़ कर सकते हैं और खुश महसूस कर सकते हैं। यह अध्ययन 'नेचर कम्यूनिकेशंस' नामक पत्रिका में छपा है।

डबल इंजन सरकार में राजस्थान का हो रहा हाई-स्पीड विकास

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरों से इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट्स में आ रही तेजी
1 लाख 22 हजार करोड़ की 29 केन्द्रीय परियोजनाओं का काम 80 प्रतिशत से अधिक पूरा

जयपुर (कासं)। राजस्थान में डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में केंद्र और राज्य के मजबूत समन्वय से इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट्स का हाई स्पीड विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने न केवल कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान हासिल किया है, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास के मोर्चे पर भी अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरों और उच्चस्तरीय बैठकों ने राजस्थान की लंबित बड़ी परियोजनाओं के तेजी से पूरा होने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। वर्तमान में केन्द्र सरकार की ओर से चल रही लगभग 2 लाख 61 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं में से 1 लाख 22 हजार करोड़ रुपये की 29 परियोजनाओं का काम 80 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है, जबकि प्रदेश में प्रगतिरत 82 केन्द्रीय परियोजनाओं पर अब तक 1 लाख 17 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी पैमाना रिपोर्ट के अनुसार बाड़मेर में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की सौगात मिलने के बाद पेट्रोकेमिकल निकासी एवं विपणन टर्मिनल का कार्य भी 99 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। जोधपुर एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों के लिए नए पैसेंजर टर्मिनल भवन का 480 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया गया है, जबकि उदयपुर एयरपोर्ट पर नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण भी 88 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसी प्रकार राजस्थान में ऊर्जा, रेलवे, सड़क परिवहन और औद्योगिक गलियारों से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। विद्युत प्रसारण और वितरण क्षेत्र में 19 प्रमुख परियोजनाओं पर 98 हजार 759 करोड़ की लागत से कार्य हो रहा है। इसमें राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन फेज-चतुर्थ की बाड़मेर कॉम्प्लेक्स 6 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट और फतेहगढ़-द्वितीय ट्रांसमिशन सिस्टम जैसी विशाल परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, रेलवे सेक्टर के तहत बीकानेर-मेड़ता-जोधपुर, अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर और सादुलपुर-रतनगढ़ रेल लाइन परियोजना सहित 22 बड़े प्रोजेक्ट्स पर 33 हजार 572 करोड़ से अधिक, राजमार्गों के 22 प्रोजेक्ट्स पर 16 हजार 241 करोड़ रुपये और शहरी सार्वजनिक परिवहन के तहत 14 हजार 222 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रगति पर हैं। राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब



के रूप में स्थापित करने के लिए औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही, माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना जैसी बड़ी परियोजना की सौगात भी मिली है। जयपुर के चारों ओर यातायात के दबाव को कम करने के लिए 11 हजार 764 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर रिंग रोड (उत्तर) परियोजना का कार्य केन्द्र सरकार के सहयोग से पूरा किया जाएगा। साथ ही, 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक की जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का कार्य भी केन्द्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि दशकों से लंबित जल संबंधी बड़ी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राम जल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों के 3 करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल और लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वहीं, यमुना, किशाऊ एवं नर्मदा जल समझौतों से राजस्थान की जल सुरक्षा बेहतर होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। डबल इंजन सरकार की इस ठोस नीति और प्रभावी क्रियान्वयन से राजस्थान न केवल बुनियादी ढांचे के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि आने वाले वर्षों में देश के सबसे विकसित राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस नीति'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकारी योजनाओं एवं निवेश प्रोत्साहन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान में आने के बाद उद्योग एवं वाणिज्य की राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने मैसर्स गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत कस्टमाइज्ड पैकेज पर रोक लगा दी है। यह छूट उक्त कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत की गई थी। रोक लगने से कंपनी को एसीबी की प्रारंभिक जांच संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने तक स्वीकृत परिलाभों के वितरण एवं छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास के साथ-साथ सरकारी संसाधनों एवं राजकीय रियायतों का उपयोग पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

दिवाली की रौनक में ट्रैफिक का पहरा, 6 से 9 नवंबर तक कई रास्ते बंद
परकोटा क्षेत्र में इन रास्तों से कर सकेंगे प्रवेश

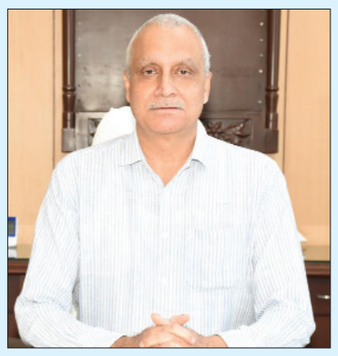
जयपुर (कासं)। जयपुर में दिवाली पर बाजारों में खरीदारी और रोशनी देखने आने वालों की भीड़ देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। परकोटा क्षेत्र में कई रास्तों पर 6 से 9 नवंबर तक शाम 6 बजे से ट्रैफिक बंद रहेगा। वहीं 8 जगह नो-व्हीकल जोन बनाए गए हैं। वहीं शहर के प्रमुख बाजारों की सड़कों पर पार्किंग नहीं होगी। पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल तय किए हैं। झोटवाड़ा रोड और स्टेशन रोड से आने वाले लोग चांदपोल अनाज मंडी में गाड़ी खड़ी कर मेट्रो से परकोटे में आ सकेंगे। सीकर रोड, अजमेर रोड और मानसरोवर की तरफ से आने वालों को भी नजदीकी मेट्रो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर मेट्रो से आने की सलाह दी गई है। परकोटा क्षेत्र में पैदल चलने वालों के लिए भी अलग व्यवस्था रहेगी।



चांदपोल गेट से आने वाले वाहन: चांदपोल बाजार से छोटी चौपड़ पहुंचकर त्रिपोलिया बाजार रोड के मीडियन के दाईं ओर से त्रिपोलिया टी-पॉइंट, चौड़ा रास्ता, न्यू गेट, रामनिवास बाग और मानप्रकाश स्लिप लेन होते हुए टोंक रोड और जेएलएन मार्ग की तरफ जा सकेंगे। अजमेरी गेट से आने वाले वाहन: किशनपोल बाजार से दाईं ओर होते हुए छोटी चौपड़ पहुंचेंगे। यहां से त्रिपोलिया बाजार रोड के मीडियन के दाईं ओर से त्रिपोलिया टी-पॉइंट, चौड़ा रास्ता, न्यू गेट, रामनिवास बाग और मानप्रकाश स्लिप लेन होते हुए टोंक रोड और जेएलएन मार्ग की तरफ जा सकेंगे। सांगानेरी गेट से आने वाले वाहन: जौहरी बाजार और बड़ी चौपड़ से होते हुए त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, न्यू गेट, रामनिवास बाग और मानप्रकाश स्लिप लेन के रास्ते टोंक रोड और जेएलएन मार्ग की तरफ जा सकेंगे। घाटगेट से आने वाले वाहन: घाटगेट बाजार और रामगंज चौपड़ से बड़ी चौपड़ होते हुए त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता और न्यू गेट से आगे जा सकेंगे। इसके अलावा चार दरवाजा और सूरजपोल गेट से भी जा सकेंगे। दिवाली के दौरान परकोटा क्षेत्र में भीड़ कंट्रोल करने के लिए छोटी चौपड़ से संजय सर्किल, अजमेरी गेट और चौगान चौराहे की तरफ जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। चौगान चौराहे से छोटी चौपड़ आने वाला ट्रैफिक भी बंद रहेगा। त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ की तरफ, न्यू गेट चौराहे से त्रिपोलिया गेट की तरफ, बड़ी चौपड़ से सांगानेरी गेट और रामगंज चौपड़ की तरफ जाने वाले वाहनों को भी प्रतिबंधित मार्गों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। सुभाष चौक से बड़ी चौपड़, गुरुद्वारा मोड़ से मिनर्वा सर्किल और घाटगेट से मिनर्वा सर्किल की तरफ भी ट्रैफिक बंद रहेगा। मिनर्वा सर्किल से एमडी रोड और धर्म सिंह सर्किल की तरफ जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। यादगार से अजमेरी गेट, त्रिमूर्ति सर्किल से आरोग्य पथ तिराहे और आरोग्य पथ तिराहे से रामनिवास बाग के अंदर जाने वाले गाड़ियों को भी प्रतिबंधित किया गया है। आरोग्य पथ से सूचना केंद्र तिराहे, पृथ्वीराज टी-पॉइंट से एसएमएस अस्पताल और अशोका टी-पॉइंट से यादगार तक जाने वाले ट्रैफिक पर भी रोक रहेगी। सेंट जेवियर चौराहे और न्यू कॉलोनी चौराहे से पांच बत्ती की तरफ जाने वाले वाहनों के साथ एमआई रोड पर गलियों से आने वाले ट्रैफिक पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान गलियों से मुख्य मार्गों पर आने वाले वाहनों को मुख्य मार्ग पर चल रहे ट्रैफिक की दिशा में ही चलना होगा।

आलोक मिश्रा ने उत्तर पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया

जयपुर (कासं)। आलोक मिश्रा ने उत्तर पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक के पद पर सोमवार, 02 नवम्बर, 2026 को कार्यभार ग्रहण किया है। मिश्रा भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा के वर्ष 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं तथा उन्हें रेलवे के आधारभूत संरचना विकास, रेलपथ अनुरक्षण एवं प्रशासन के क्षेत्र में 34 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार अपर महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आलोक मिश्रा उत्तर रेलवे में उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे। इससे पूर्व उन्होंने उत्तर रेलवे में मुख्य ट्रैक इंजीनियर के पद पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। अपने तीन दशक से अधिक के गौरवशाली सेवाकाल में मिश्रा ने रेलवे के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए रेल अवसंरचना के विकास, रेलपथ की गुणवत्ता एवं अनुरक्षण तथा परिचालन संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न चुनौतीपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता एवं कार्यकुशलता का परिचय दिया है। आलोक मिश्रा के व्यापक अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता एवं प्रशासनिक कुशलता से उत्तर पश्चिम रेलवे की विकास परियोजनाओं, रेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलगा।



केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता सचिव से की मुलाकात

ऐतिहासिक जल जीवन मिशन 2.0 पर केंद्र से राजस्थान ने उठाया 3 हजार करोड़ का मुद्दा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पेयजल सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों के क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक के. मीना से मुलाकात की।

सीजीओ परिसर में हुई बैठक में राजस्थान में जल जीवन मिशन 2.0 से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने मिशन के तहत राजस्थान से संबंधित योजनाओं के आंकड़ों का समय पर मिलान करने तथा प्रदेश के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की राशि समय पर जारी करने का विषय रखा। योजनावार आंकड़ों के समन्वय के लिए राज्य की ओर से प्रस्तुत समेकित प्रस्ताव से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में जल जीवन मिशन 1.0 और 2.0 के बीच मार्च 2024 से मार्च 2026 की अवधि में हुए व्यय से संबंधित राशि जारी करने पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने राजस्थान के जल जीवन मिशन 2.0 से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा को सकारात्मक बताया।

मुख्य सचिव ने केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव से की मुलाकात-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण



और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयासों के क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल से मुलाकात की। बैठक में जयपुर में दिसंबर 2026 में राष्ट्रीय सरस मेले के आयोजन तथा वीबी-जी राम जी की प्रगति पर चर्चा हुई। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) द्वारा राष्ट्रीय सरस मेला 2026-27 का आयोजन 25 दिसंबर 2026 से 11 जनवरी 2027 तक जयपुर में प्रस्तावित है। इस 18 दिवसीय मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र के दक्षिणी परिसर, शिल्पग्राम एवं इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर में करने की तैयारी है।

मेले के आयोजन के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मेले में राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए लगभग 750 से 800 स्टॉल प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही खानपान के लगभग 50 स्टॉल, हस्तशिल्प निर्माण का सजीव प्रदर्शन, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं।

आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, पारंपरिक हस्तशिल्प एवं लोक कलाओं को मंच उपलब्ध कराना तथा महिला उद्यमियों के लिए स्थायी बाजार संपर्क विकसित करना है। इसके लिए मेले के दौरान क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन भी प्रस्तावित है। राजसखी ब्रांड के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के अवसर भी उपलब्ध होंगे। बैठक में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), अर्थात वीबी-जी राम जी की प्रगति पर भी विचार-विमर्श किया गया।

कांग्रेस के लोकतंत्र के मॉडल में मतपत्रों की चोरी, गहलोत दें जवाब: मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस द्वारा वोट चोरी के आरोपों को लेकर किए जा रहे आंदोलन पर पलटवार करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और राजनीतिक विडंबना है कि वोट चोरी के आरोपों से घिरी कांग्रेस आज खुद वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन करने का ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोकतंत्र मॉडल में मतपत्रों की चोरी आती है, जिसका हाल ही में जोधपुर जिले की बिलाड़ा पंचायत समिति के भावी ग्राम पंचायत क्षेत्र में एनएसयूआई के नेता सुनील चौधरी पर मतपत्र चोरी कर मतदान केंद्र से बाहर ले जाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मुहर लगाने का मामला सामने आया है। आरोपित चौधरी अशोक गहलोत का नजदीकी व्यक्ति है। लोकतंत्र की बार बार दुहाई देने वाले गहलोत जवाब दें, क्या ऐसा ही मॉडल वो पूरे देश में चाहते है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग और जनादेश के अपमान से भरा पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को दूसरों पर



आरोप लगाने से पहले अपने अतीत और वर्तमान के कारनामों पर आत्ममंथन करना चाहिए। राठौड़ ने कहा कि गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस के विभिन्न नेताओं पर समय-समय पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भावी पंचायत का मामला चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस को इस मामले में जवाबदेही तय करनी चाहिए, न कि वोट चोरी के नाम पर राजनीतिक नौटंकी करके जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाना चाहिए। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस आज लोकतंत्र की रक्षा का दावा कर रही है, लेकिन देश का इतिहास गवाह है कि इसी कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 356 का 93 बार इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। यह लोकतांत्रिक जनादेश और संघीय व्यवस्था के सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिस पार्टी ने लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया, उसका आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा हितैषी बनने का प्रयास जनता को भ्रमित करने वाला है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने कहा कि रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली और प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। मंच से नेताओं के भाषण जारी थे, लेकिन सामने कुर्सियां खाली पड़ी थीं। यह दृश्य कांग्रेस के प्रति जनता की घटती रुचि और उसके राजनीतिक एजेंडे से लोगों की दूरी को दर्शाता है।

जब जनता ही कांग्रेस के प्रदर्शन में भाग लेने नहीं पहुंची, तब पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए भीड़ दिखाने का सहारा लिया। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा सोशल मीडिया पर प्रयागराज की भीड़ वाली तस्वीर साझा कर उसे कांग्रेस के प्रदर्शन से जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया।

न्यूज इनबॉक्स

दीपावली पर जयपुर मेट्रो की सौगात, रात 12:30 बजे तक दौड़ेंगी ट्रेनें

जयपुर (कासं)। जयपुर मेट्रो राष्ट्रीय पर्वों, त्यौहारों एवं उत्सवों के दिनो में भी जनता के प्रति अपना सामाजिक सरोकार पूरी तरह निभाता रहा है। इसी कड़ी में आगामी दीपावली सीजन पर दिनांक 03.11.2026 से 11.11.2026 तक जयपुर मेट्रो ट्रेन के फेरों की संख्या वर्तमान संख्या 202 से बढ़ाकर 214 कर दी गई हैं। दीपावली को लेकर परकोटे के मुख्य बाजारों में रोशनी की सजावट को देखने एवं खरीददारी हेतु काफी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक एवं शहरवासियों के आगमन को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया हैं। शहर में दिनांक 06.11.2026 से 09.11.2026 तक यातायात के सुगम संचालन हेतु परकोटा क्षेत्र में चलने वाले सिटी/मिनी बसों, ऑटो एवं ई-रिक्शा इत्यादि का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। अत: जयपुर मेट्रो प्रशासन द्वारा शहरवासियों की सुविधा हेतु जयपुर मेट्रो के संचालन फेरों की संख्या बढ़ाते हुए अन्तिम मेट्रो ट्रेन का संचालन मानसरोवर एवं बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से रात्रि 12:30 बजे तक किये जाने का भी निर्णय लिया गया हैं। जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक वैभव गालरिया ने मेट्रो प्रशासन की और से जयपुरवासियों तथा मेट्रो यात्रियों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की और बताया कि मेट्रो यात्री दिनांक 03.11.2026 से 11.11.2026 तक मेट्रो संचालन की इस व्यवस्था का लाभ उठा पाएंगे।

गोबर और मिट्टी के दीयों से रोशन होगी दीपावली

जयपुर (कासं)। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वॉकल फॉर लोकल' के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। प्रदेश के पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने आमजन से अपील की है कि इस बार दीपावली पर अपने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सजावट के लिए गाय के गोबर और मिट्टी से बने दीयों व कलाकृतियों का ही उपयोग करें। मंत्री कुमावत ने कहा कि गो-उत्पादों और पारंपरिक मिट्टी के दीयों को अपनाकर हम न केवल अपनी संस्कृति को सहेजेंगे, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और गरीब तबके को सीधा आर्थिक संबल मिलेगा। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंदिरों के लिए विशेष बजट-

इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बार दीपावली पर देवस्थान विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मंदिरों की विशेष साज-सज्जा और लाइटिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट जारी किया गया है।

धार्मिक पर्यटन और आस्था को मिल रहा बढ़ावा-

पिछले कुछ वर्षों का उल्लेख करते हुए कुमावत ने प्रसन्नता जताई कि राज्य सरकार द्वारा हर साल प्रदेश के आराध्य देवों और प्रमुख मंदिरों की सजावट के लिए निरंतर योगदान दिया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों से न केवल त्योहारों की रौनक बढ़ी है, बल्कि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक पर्यटन को भी एक नया विस्तार मिला है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार की दीपावली प्रदेश में समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता का नया संदेश लेकर आएगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय, में 15 दिसम्बर को आयोजित होगी पेंशन अदालत

जयपुर (कासं)। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय से सेवानिवृत्त रेलकर्मियों की पेंशन एवं रेलकर्मियों के आश्रित परिवार पेंशनरों की पेंशन से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु वर्ष 2026 की पेंशन अदालत का आयोजन 15 दिसम्बर 2026 को 11:00 बजे उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, प्रधान कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी एवं अधिकारी तथा दिवंगत रेलकर्मियों के आश्रित परिवारजन, जिन्हें पेंशन अथवा परिवार पेंशन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत है, वे निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 15 नवम्बर 2026 तक प्रधान कार्यालय, जयपुर में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा करवा सकते हैं। पेंशनर एवं परिवार पेंशनर अपनी शिकायतों के निस्तारण हेतु निर्धारित तिथि को आवेदन पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हो सकते हैं।

राजस्थान पुलिस ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प, ऊर्जा बचत पर जोर

जयपुर (कासं)। ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक के तहत पुलिस मुख्यालय एवं राजस्थान पुलिस अकादमी में पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सतत जीवनशैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। 01 से 07 नवम्बर, 2026 तक आयोजित इस सप्ताह के दूसरे दिन सोमवार को ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था) संजय अग्रवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को 'मिशन लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' की शपथ दिलाई, वहीं राजस्थान पुलिस अकादमी में ऊर्जा बचत के प्रति जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। पुलिस मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर स्थित पश्चिम चौक में आयोजित कार्यक्रम में महानिदेशक पुलिस श्रीमती मालिनी अग्रवाल सहित अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वीके सिंह, रुपिंदर सिंघ, बिपिन कुमार पाण्डेय, संजीब कुमार नार्जरी, एस. सेंगाथिर, भूपेंद्र साहू एवं हवा सिंह घुमरिया सहित पुलिस मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मंत्रालयिक कार्मिकों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। शपथ के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, अपशिष्ट में कमी लाने तथा दैनिक जीवन में सतत जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया गया।

कार्यालय नगर पालिका, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)
E-Mail – mbshahpura.bhl@gmail.com Ph. 01484-222212
क्रमांक : स्टोर/नपाशा/26-27/221 दिनांक : 27/10/2026
:: Notice Inviting Bid ::
Bids for services works in Municipal area of Shahpura (Bhilwara) are invited from interested bidders upto 11.00 AM, 05-11-2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal(http://sppp.raj.nic.in) of the state.
UBN:-DLB2627A9229
(DLB2627SLOB23340)
Executive Officer
Municipal Board Shahpura
Raj.Samwad/C/26/12717

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक कैलाश त्रिवेदी के लिए उदय प्रिन्टर्स 43-ए, माली कॉलोनी चांदपोल बाहर जयपुर से मुद्रित एवं डी-38, प्रधानपथ, चौमू हाउस, सी स्कीम, जयपुर से प्रकाशित। सम्पादक कैलाश त्रिवेदी* । *पीआईबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार।
फोनः 0141-4038281, Email:- lokjeewanjpr@gmail.com भीलवाड़ा कार्यालयः 207-214, नागौरी गार्डन, लोकजीवन कॉम्पलेक्स, भीलवाड़ा। फोनः 01482-355985, Email:- lokjeewan@gmail.com, मो. 8306792625